सुकवा
भोर का तारा

कृषक उत्पादक संगठनों की त्रैमासिक पत्रिका

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा प्रकाशित | प्रवेशांक | वर्ष-1, अंक-1, माह-जनवरी से मार्च 2014
निशुल्क वितरण हेतु

अपनी बात

कृषक उत्पादक संगठन अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एफपीओ) के गठन की योजना के परिणाम अब सर्वविदित है। एसएफएसी ने जो सपना देखा था, वह धरातल पर साकार हो रहा है। देशभर में छोटे और सीमांत किसानों के ये समूह सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। एसएफएसी ने वर्ष 2011–13 के लिए 225 एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा था, जिसके विरुद्ध अब तक 107 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। साथ ही 118 के गठन की प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के जरिए जहां 233548 किसानों को प्रेरित किए जाने का लक्ष्य था, वहीं अब तक 237821 किसानों को प्रेरित किया जा चुका है। यानी लक्ष्य से बहुत ज्यादा। एफपीओ की सफलता के साथ–साथ हजारों की संख्या में किसानों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। किसी भी गांव में किसानों का सबसे बड़ा प्रेरणा स्त्रोत किसान ही होता है। एक दूसरे की सफलताएं उन्हें अनुकरण की प्रेरणा देती हैं। एक–दूसरे से वे सीखते हैं। एक दूसरे के समस्याएं वे ही सुलझाते हैं। सफलता का एक चरण पूरा कर लेने के बाद एसएफएसी ने एक ऐसी पत्रिका के प्रकाशन की कल्पना की, जो एक एफपीओ को दूसरे एफपीओ की कहानी दुनिया को सुना सके। चुनौतियों से निपटने के अनुभवों को साझा कर सके। इस पत्रिका का एक नाम संवदिया भी हो सकता था, क्योंकि मूलतः इसका काम यही है। लेकिन हम इसे सुकवा नाम दे रहे हैं। सुकवा यानी भोर तारा। यानी छोटे और सीमांत किसानों के शोशण से मुक्ति की सुबह की शुरुआत। यानी तकनीक और सूचनाओं के नये युग की शुरुआत । यानी कुछ नया कर गुजरने की शुरुआत । उम्मीद है कि यह पत्रिका अपने उद्देश्यों में कामयाब होगी।

– संपादक

कृषक उत्पादक संगठन (FPO)

छोटे और सीमांत किसानों को खेतों से लेकर बाजार तक तरह–तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों की जरूरत होती है। कृषक उत्पादक संघ यानी एफपीओ की अवधारणा इन किसानों को संगठित कर समस्याओं को निराकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है। यह एक ऐसी संस्थागत सुविधा है जो किसानों को सामूहिक रूप से फायदा पहुंचाती है। उन्हें एक अच्छा उत्पादक बनाती है और सुनिश्चित करती है बाजार के साथ अपने रिश्ते को लेकर किसान ज्यादा जागरुक और शोषणमुक्त हों। कृषक उत्पादक संघ एक स्वैच्छिक संगठन हैं जिसमें सदस्यता हासिल कर किसान बेहतर परिणाम ला सकते हैं। ऐसे संगठन देश के 25 राज्यों में सक्रिय है, लाखों किसानों को इसका फायदा मिल रहा है।

वर्तमान में कृषक उत्पादक संघ को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए उन्हें लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अब तक हजारों बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें लाखों किसानों ने भागीदारी की है। इन बैठकों और प्रशिक्षणों के जरिए किसानों ने अपने अनुभवों का आदान–प्रदान किया है। इस तरह उनके जमीनी अनुभवों से भी कृषि सुधार की दिशा में उनका महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी हासिल हुए हैं। आज एफपीओ की अवधारणा को लेकर देश को उम्मीद बंधी है कि इसके जरिए बेहतर कृषि व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। लगातार मिल रही सराहनाओं ने कृषक उत्पादक संघ की नींव को और भी अधिक मजबूत किया है।

...और सुबह हो गई

अब इसे तोड़कर बताए कोई–बूढ़े बाबा ने कहा। सबने कोशिश की। तोड़ कोई न सका। टूटती भी कैसे, एक–एक सूखी लकड़ियां मिलकर गठ्ठर हो चुकी थीं। एक अकेली लकड़ी को कोई भी पट्ट से तोड़ सकता है।

कमजोरों को ताकतवर बनाने का यह पुराना नुस्खा है। किसे नहीं पता। लेकिन एकजुट होने की कोशिश ही कोई नहीं करता। और जहां भी थोड़ी–सी कोशिशें हुईं, वहां तो चमत्कार ही हो गया। राजगढ़ से किस्से की शुरुआत करते हैं। इस इलाके के किसानों पर कालीसिंध और नेवज नदियां अपनी ममता लुटाती हैं। ज़मीन भी ऐसी कि सोयाबीन और सब्जियां भरपूर पैदा होती हैं। संतरे की भरपूर पैदावार है। लेकिन सबकुछ होने के बाद भी यहां के हजारों किसानों की ज़िंदगी आसान नहीं थी। कम. रतोड़ मेहनत के बाद भी वे ज़माने के साथ कदमताल नहीं कर पाते थे। पैदावार कैसे बढ़ाई जाती है, फसलों को कैसे बचाना चाहिए, ये सब उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं थी। बुजुर्गों ने सब सिखा रखा है। दिक्कत यह थी कि छोटे–छोटे खेतों में इतनी महंगी तकनीकें अपनाई कैसे जाएं, और फसल बचा भी ली, पैदावार बढ़ा भी ली तो बाजार में सही कीमत मिलने से रही। छोटे खेतों से थोड़ी मात्रा में फसल को बाजार तक पहुंचाना ही झमेला है। इसका बिचौलिए पूरा फायदा उठाते। फसलों की सही कीमत तो मिलती ही नहीं थी, और भी बहुत–सी परेशानियां थीं। परेशानियां ही परेशानियां।

तब परेशान किसानों ने पुराने नुस्खे को आजमाने की सोची। छोटे–छोटे खेतों वाले किसान एकजुट हुए। मिलकर खेती करने लगे, एक दूसरे से मशविरा कर फसलें बोने लगे। एक दूसरे की ज़मीनों का खयाल रखना शुरू किया, नुकसान की निगरानी शुरू की। परिणाम यह हुआ कि बाजार तक ले जाने के लिए उनके पास अब एक ही किस्म की भरपूर उपज होने लगी। जब बड़े पैमाने पर उपज उपलब्ध थी तो सोचा कि क्यों न सही बाजार का पता लगाया जाए। सही बाजार तक पहुंचे तो अच्छा दाम मिलने लगा। यानी दोहरा फायदा। हर किसान का उत्पादन बढ़ा, पैसा भी ज्यादा मिलने लगा। मुस्कुराहटें भला कैसे न खिलतीं।

लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हो गया। यह चमत्कार सरकार की एक योजना ने किया। यूं तो किसान इसे संगठन बनाना कहते हैं, लेकिन दरअसल ये एफपीओ हैं। यानी फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन। भारत सरकार के लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) ने एनजीओ के माध्यम से किसानों का यह संगठन तैयार किया है। यह एक संगठन भर नहीं हैं, बल्कि किसानों की एक कंपनी है। कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड। इस कंपनी को किसान ही चलाते हैं। वे ही इसके संचालक मंडल का गठन करते हैं। वे ही कंपनी के कर्मचारी तय करते हैं। कंपनी और बाजार के बीच का रिश्ता, लेन–देन, घाटा–मुनाफा सबकुछ वे ही तय करते हैं। इस कंपनी में उन्हीं के शेयर लगे हुए हैं, वे ही योजनाएं बना रहे हैं कि थोड़े मुनाफे को ज्यादा में बदलने के लिए अब क्या किया जाना चाहिए।...सतही तौर पर किसी एक किसान की परेशानी, शोषण और नुकसान का अनुमान लगाना तब भी सहज है। लेकिन व्यापक रूप में देश को हो रही क्षति की तस्वीर डरावनी है। एसएफएसी ने एफपीओ की परिकल्पना इन्हीं परिस्थितियों में बदलाव को लेकर की थी। छोटे किसानों को सूचनाओं की विषमता से बचाने के लिए। पानी और श्रम जैसी जरूरतों के लिए अनियमित स्त्रोतों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए। उन्हें नियमित और विश्वसनीय तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने के लिए। साहूकारों के महंगे कर्ज से बचाने के लिए। और तमाम सरकारी योजनाओं को उनके घरों–खेतों तक पहुंचाने के लिए। कामयाबी यह मिली कि एफपीओ की ताकत ने बाजार में खरीदारों के दबदबे पर चोंट कर दी है। वे समझ रहे हैं कि माल जिसका है, कीमत तय करने का अधिकार भी उसी का होना चाहिए। वे खेती–किसानी के कानूनों को पढ़ रहे हैं, राजस्व मामलों को सुलझा रहे हैं, पटवारियों–तहसीलदारों से संगठित होकर बातें कर रहे हैं।

और उधर बिहार में..

छोटे और सीमांत किसानों के संगठन की कहानी का एक और पन्ना बिहार का है। यहां किसानों की चार कंपनियां बन चुकी हैं। इनके जरिये 3 हजार 273 किसान एकजुट हुए हैं। इनका चमत्कार देखिए–

किसानों ने टमाटर के एक ऐसे बीज को केवल 22 हजार रुपए किलो में हांसिल किया जिसकी कीमत बाजार में 32 हजार रुपए किलो है। इन्हीं किसानों ने बाजार में पता किया कि चिल्हर बेचने वाले इसे किस भाव में बेच रहे हैं। थोक में यह बीज कितने में मिलेगा। और यदि कंपनी से सीधे बात की जाए तो कितना मुनाफा हो सकता है। इन किसानों ने अपनी कंपनी के जरिए बीज–कंपनी से सीधे बात की और 20 हजार रुपए किलो के भाव से बीज खरीद लिया। यह बीज किसानों की कंपनी ने 22–22 हजार रुपए

प्रतिकिलो में अपने शेयर होल्डर्स को उपलब्ध कराया। यानी अपनी कंपनी के खाते में उन्होंने 2 हजार रुपए प्रति किलो का मुनाफा दर्ज कराया। यानी मुनाफा ही मुनाफा।

इसी तरह की कई रणनीतियां और योजनाएं बनाते हुए बख्तियारपुर किसान प्रोड्यूसर संघ, बाढ़ किसान प्रोड्यूसर संघ, एकंगरसराय कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हरनौद किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अपनी नयी दिशाएं तय कर रही है। इन कंपनियों को प्रेरित किया कौशिल्या फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने। फाउंडेशन कहता है कि किसानों को एकजुट करने की कोशिशें 2011 में शुरू हुई थीं। शुरुआत में किसान संगठन का महत्व नहीं समझते थे। उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, प्रदर्शन यात्राएं कराई गईं, आहिस्ता–आहिस्ता वे एकजुट हुए। कंपनी के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। आज लोग अपनी कंपनी का महत्व समझते हैं। छोटे–छोटे खेतो के मालिक के मालिक ये किसान बाजार में अपनी ही फसल सही कीमत पर नहीं बेच पाते थे, आज उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वे किसी से भी बिजनेस की बात कर लेते हैं। इन किसानों ने अपने उत्पादों के लिए कलेक्शन सेंटर्स खोल रखे हैं। एसएफएसी की ओर से तयशुदा मार्केटिंग कंपनी केजीपीएल इन किसानों से उनके कलेक्शन सेंटर्स पर ही सब्जियां खरीद रही हैं। अब ज्यादातर किसान बाजार में अपने उत्पाद नहीं बेचते। अपने ही कलेक्शन सेंटर में उन्हें अच्छा रेट मिल जाता है। केजीपीएल और किसानों के बीच में कोई बिचौलिया जो नहीं है।

किसानों में जागरुकता आई है कि सरकारी योजनाओं का अधिकतम फायदा उठाकर वे और ज्यादा तरक्की कैसे कर सकते हैं। इन किसानों ने नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव (एनवीआई) के तहत बांस से बने पाली हाउसेस हांसिल कर लिए हैं। यानी बिहार के क्षितिज पर भी सुकुवा टिमटिमा रहा है।

एफपीओ – बख्तियारपुर किसान प्रोड्यूसर संगठन, बाढ़ किसान प्रोड्यूसर संगठन,
एकंगसराय कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हरनौद किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बिहार
स्रोत संस्था – कौशल्या फाउंडेशन

अपनी दुकान, अपना दाम

राजस्थान में सब्जी का उत्पादन करने वाले किसानों ने बाजार की मार से बचने के लिए नयी तरकीब ढूंढ निकाली। सब्जी की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, खादों, बीजों की खरीदारी में उठाना पड़ता है। सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री को समझ तो होती नहीं, इसलिए खुले बाजार के व्यापारी कई बार उन्हें घटिया सामान बेहद ऊंची कीमतों पर थमा देते हैं। संगठन बन जाने के बाद किसानों ने सबसे पहले इसी नुकसान से उबरने की सोची। उन्होंने तय किया कि किसानों को जिन भी चीजों की जरूरत होगी, अब उन्हें किसानों की कंपनियां ही उपलब्ध कराएगी। टौंक जिले के मालपुरा विकासखंड की केदारनाथ किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने इसकी पहल की। उसने लायसेंस हांसिल किया और पचेवर नाम के गांव में दुकान खोल दी। यह एक ऐसा गांव था, जहां इस तरह की दुकान थी ही नहीं। इस दुकान की अपनी विशेषता है। यह तरह–तरह की सामग्री संग्रहित करके नहीं बेचती, बल्कि वहीं चीजें बेचती हैं जिनकी फौरीतौर पर किसानों को जरूरत होती है। ये जरूतें किसानों के माध्यम से ही कंपनी को पता चलता हैं। इससे फायदा यह कि दुकान में लागत कम आती है। खुले बाजार में बिकने वाली चीजों की तुलना में यहां की चीजें भरोसेमंद तो होती ही हैं, बेहद सस्ते में भी मिल जाती है। दुकान की लोकप्रियता का आलम यह है कि बीते 10 जुलाई को दुकान के उद्घाटन से पहले ही पूरा का पूरा शुरुआती स्टाक बिक चुका था। इस तरह किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक, निंदानाशक उपलब्ध हो जाता है। उन्हें भटकना नहीं पड़ता। एक दूसरी कंपनी गणेश किसान एग्रोप्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भी अब इसी तरह की दुकान खोलने की तैयारी कर रही है। उसने भी लायसेंस हासिल कर लिया है। जल्द ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। राजस्थान मे इंडियन सोसायटी आफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स (आईएसएपी) नाम के एनजीओ के जरिए एसएफएसी ने राजस्थान में ऐसे ही 10 एफपीओ तैयार किए हैं। इनमें से पांच सब्जी उत्पादक किसानों के है तो पांच दलहन पैदा करने वाले किसानों के। ये सभी संगठन अपने–अपने स्तर पर अपनी–अपनी दिक्कतों का लेखा–जोखा तैयार कर रहे हैं। वे रणनीति बना रहे हैं कि इन दिक्कतों से कैसे उबरा जा सकता है। अनियमित बाजार, क्रेताओं के नियंत्रण और सूचनाओं की बाधाओं से कैसे निपटा जा सकता है। सब्जी उत्पादक किसान जहां अब अपने उत्पाद की बिक्री के लिए सही नेटवर्क तैयार करने की सोच रहे हैं, वहीं दलहन के किसान सोच रहे हैं कि क्यों न खुद ही दाल मिल लगा ली जाए।

एफपीओ – केदारनाथ किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मालपुरा, गणेश किसान एग्रोप्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
स्रोत संस्था – इंडियन सोसायटी आफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स

खैरासी, खेत और टुनटुने

आप घीसालाल जी मालवीय को नहीं जानते। घीसालाल जी भी आपको नहीं जानते। लेकिन यदि आप खैरासी के पांच–दस कोस में होते तो यह हो ही नहीं सकता था कि आप एक–दूजे को नहीं जानते।

घीसालाल जी को होती है चप्पे–चप्पे की खबर। उम्र 65–70 तो होगी ही। तब भी पांव घर पर नहीं टिकते। किस गांव में, किस घर में किसे किस तरह की समस्या है, सब पता है। आदमी ही नहीं, खेत–खार की सेहत का भी उन्हें सब पता होता है। राजगढ़ (मप्र) के इस गांव में पिछले दो–तीन सालों में खेती–किसानी को लेकर चेतना की जो नई बयार बह रही है, आजकल वे उसी में मस्त हैं। उनकी जेब में एक पुराना मोबाइल हैंडसेट समय–समय पर टुन–टुनाता रहता है। उनके मैसेज बाक्स में कभी मौसम का हाल टपकता है, तो कभी किसानी की कोई और महत्वपूर्ण खबर। और यह टुनटुना घीसालाल जी की जेब से होता हुआ गांव–इलाके के कई किसानों की जेबों तक जा पहुंचा है। बावजूद इसके कि बहुत से किसान छोटे जोत के हैं, घरों–घर ट्रेक्टर है। सबने बैंक से कर्ज ले रखा है, और बैंक खुले हाथ इनकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें दिया पैसा डूबता नहीं है। राजगढ़ के खुद्दार किसान कर्ज का मतलब जानते हैं और यह भी कि किसी का दिया हुआ न लौटाना कितनी फदिहत की बात है।

देश के बहुत से इलाकों में खेती को लेकर किसानों का दृष्टिकोण बदल रहा है। खैरासी जैसे कई गांवों में खेती में ही नयी तकनीकें नहीं अपनाई जा रहीं, आपस के रिश्तों में भी वे नये तकनीक अपना रहे हैं। वे सीख रहे हैं कि छोटे किसानों को बाजार कैसे निगल लेता है, और बाजार से यदि अपनी उपज का सही दाम वसूलना हो तो क्या किया जाए। हल–बाखर ही नहीं अब तो मोबाइल और इंटरनेट भी खेती के औजार बन गए हैं। उत्पादन दो गुना तक बढ़ा है। जो नौजवान पढ़लिखकर नौकरियां तलाश रहे थे, वे कहते हैं–मजा तो खेती में ही है। खैरासी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। घीसालाल जी का आशीष आप पर भी बरसे।

हाथ आया खजाना....

देवसिंह की लाड़ी रामकुंवर को तो जैसे खजाना मिल गया। खजाना ही तो है, जिनता खोदोगे उतने पैसे बनते जाएंगे। पैसे बचाना और पैसे बनाना एक ही बात है। रामकुंवर को अपने खेतों के लिए अब खाद खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उसके खेत में बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पिट जो बन गया है। अब तो कचरे से भी रकम बनेगी। एक और फायदा हुआ, रासायनिक खाद से मुक्ति मिली। वरना जमीन का बुरा हाल हो रहा था। जमीन सुधरेगी तो उपज बढ़ेगी। पैसा ही पैसा। रामकुंवर ही नहीं राजगढ़ की दोनों प्रोड्यसर कंपनियों 85 लोगों ने पिट स्थापित करवा लिए हैं। एफपीओ के जरिए ही उन्हें पता चला कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ऐसे पिट बनवाने के लिए सरकार मदद देती है। 3 हजार रुपया खुद लगाओ तो 3 हजार सरकार दे देगी। एक पिट से 60–65 दिनों में 15 क्विंटल जैविक खाद मिल जाती है। साल में 60 क्विंटल। इससे पहले तक तरह–तरह की रासायनिक खादों में ही बहुत पैसा निकल जाता था। सबसे ज्यादा खैरासी के लोगों ने बर्मी कंपोस्ट पिट बनवाए हैं। गोलाखेड़ा, नारायनिया, हालाखेड़ी आदि गांव भी पीछे नहीं रहे। इन लोगों को जो फायदा मिल रहा है, उसे देखकर दोनों कंपनियों में शामिल इनसे भी दुगुने लोग अगले सिजन का इंतजार कर रहे हैं। पिट वे भी बनवाएंगे।

एफपीओ के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की चेतना इसलिए जागी, क्योंकि सूचनाएं गांववालों तक आसानी से पहुंचने लगी। बर्मी कंपोस्ट ही नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बीज ग्राम योजना का भी भरपूर लाभ राजगढ़ ने लिया है। यह योजना किसानों में अच्छे बीजों के प्रति आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन की न्यूट्री फार्म योजना के तहत इन किसानों ने मक्का का प्रदर्शन देखा है। हालांकि बारिश में फसल खराब हो गई, पर अनुभव तो मिला।

दो गुना हो गया उत्पादन

खैरासी के घीसालाल मालवीय लगभग चहकते हुए कहते हैं–पहले से दो गुना ज्यादा फसल लेते है साहब। कैसे? खेतों की गहरी जुताई, बीजों का सही उपचार, कीटनाशकों का सही प्रयोग और समय–समय पर विशेषज्ञों से जानकारी मिली। मिट्टी का परीक्षण कराया। एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल इस बार सोयाबीन की जोताई बुवाई में किया गया। कुछ ही किसानों ने इसे आजमाया। परंपरागत जुताई, बुवाई से हटकर अपनाई गई इस तकनीक का असर किसानों ने देखा। बारिश में जहां कई किसानों की सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले खेत मुस्कुराते रहे। खेतों में मशीन ने पानी की निकासी के लिए नालिया जो बना दी थीं। बढ़ते हुए उत्पादन और लाभ की ओर जा रही खेती ने बहुत से नौजवानों की दिशा वापस खेतों की ओर मोड़ दी है। राजगढ़ प्रोड्यूसर कंपनी के नौजवान डायरेक्टर हुकुमसिंह सौंधिया जी 23 साल के हैं। उन्होंने अपनी सरकार चुनने के लिए पहली बार मतदान किया है। लेकिन कंपनी से जुड़े किसानों ने उन्हें पहले ही चुनकर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भेज दिया था। उनके जैसे 10 डायरेक्टर हैं। सबके सब नौजवान। यही लोग प्रेरक स्वयं सेवी संगठनों के साथ योजनाएं बनाते हैं। किसानों की बैठकें लेते हैं। उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को टटोलते हैं। हुकुमजी कहते हैं कि सिर्फ दो सालों में ही इलाके की खेती संवर गई है। पहले नौकरी का खयाल आ भी जाया करता था। अब सोचते हैं कि फायदा खेती में ही है।

दो साल में ही बहुत कुछ बदल गया। खेती में बहुत फर्क आया है। हमने जो समूह बनाया है उसकी वजह से उत्पादन बढ़ा है। हम बहुत खुश हैं। हमने कंपनी बना ली है, उसे हम ही चलाते हैं।

घीसालाल मालवीय, किसान (खैरासी, राजगढ़, मप्र)

हर महीने होने वाली बैठकों में हमें जानकारी मिल जाती है कि अब करना क्या है। कीड़ों को नियंत्रित कैसे करना है, खरपतवार से कैसे निपटना है। कब कौन से कीड़े का प्रकोप हो सकता है। समूह बनाकर हम बहुत फायदे में हैं।

बद्रीविशाल, युवा किसान (खजूरी, राजगढ़, मप्र)

अच्छा लगता है। अब खेती में फायदा दिखता है। गांव के दूसरे किसान भी अब कंपनी में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। उनके भी नये समूह बना रहे हैं।

बीरम सिंह, किसान (खैरासी, राजगढ़, मप्र)

छलक रहा आत्मविश्वास

केवल दो सालों में ही प्रेरक स्वयं सेवी संगठन एडीएस के साथ मिलकर किसानों ने जो कुछ सीखा और समझा, उससे वे आत्मविश्वास से लबरेज हैं। किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने की जरूरत अब नहीं रह गई है। इन समूहों के किसानों की सफलता देखकर अब वे किसान भी बोर्ड आफ डारेक्टर्स से संपर्क कर रहे हैं, जो समूह से बाहर थे। एनजीओ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब जब स्वतंत्र रूप से बोर्ड आफ डायरेक्टर को कंपनी चलाने का अवसर मिल रहा है तब भी उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। नौजवान सदस्यों का कहना है कि दो सालों में हमने जान लिया कि किसानों को किन किन विभागों और सरकारी संस्थाओं से क्या क्या मदद मिल सकती है। फसल का सामूहिक उत्पादन और संग्रहण कैसे किया जाता है। बाजार कैसे तलाशा जाता है। बीज–खाद की व्यवस्था कम कीमत पर कैसे की जाती है। कंपनी को चलाने के लिए कर्मचारियों भी जरूरत पड़ेगी। उन्हें वेतन देना होगा। इसमें भारी–भरकम खर्च हो सकता है, वे जानते हैं। लेकिन कहते हैं–हम कर लेंगे। अगले सीजन से बीज का प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। आगे और भी योजनाएं हैं।

जो सोचा न था...

राजगढ़ (मप्र) के किसानों ने सोचा भी न था कि जिन छोटे–छोटे खेतों से गुजारा भी मुश्किल था, वही खेत उन्हें इतना दे सकते हैं कि चार पैसे अपने गुल्लक में भी डाल सकें। इन किसानों ने यह भी कल्पना नहीं की थी कि इन्हीं छोटे खेतों की बदौलत वे बाजार में तन कर खड़े हो सकते हैं। बड़ी–बड़ी बीज–खाद कंपनियों की आंखों में आंखें डालकर सौदा कर सकते हैं। अब उन्हें इस बात का अहसास हो रहा है कि वे खुद एक कंपनी के मालिक है। अब वे सिर्फ अपने खेत की ही चिंता नहीं करते, उनकी चिंता में यह कंपनी भी शामिल हो गई है। इन किसानों को उम्मीद है कि जिस रोज यह कंपनी मुनाफा कमाने लगेगी, उनके दिन और फिरेंगे। किसानों का शेयर जो है, मुनाफे में भी शेयर तो होगा ही। कंपनी के हितों और भविष्य की योजनाओं के लिए सुझाव–प्रस्ताव कभी संचालक मंडल से समूहों तक आते हैं तो कभी समूहों से संचालक मंडल तक। बैठकें नियमित हुआ करती हैं। नियम बना रखा है कि तीन महीने में एक बार संचालक मंडल की बैठक तो होगी ही। लेकिन यह नियम ताक पर रह जाता है, संचालक मंडल के सदस्य हर महीने आ जुटते हैं। अपने खर्चे पर।

एफपीओ–राजगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मां जालपा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजगढ़, मध्यप्रदेश
स्रोत संस्था– एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस

खेतों ने चढ़ाई बाहें तो सहम गया बाजार

रायपुर (हरि भूमि, 01 जनवरी 2014)। अक्सर ऐसा ही होता है। परिवार बढ़ता है तो खेत छोटे हो जाते हैं। खेत छोटे होते हैं तो आमदनी सिकुड़ जाती है। और जब आमदनी सिकुड़ जाती है तो आखिरकार पलायन करना पड़ता है। खेत–खार बिकने लगते हैं। जिंदगी शोषण को दुष्चक्र में फंसती ही चली जाती है।

देशभर में यही हो रहा है। पारिवारिक बंटवारों और दिगर परिस्थितियों की वजह से छोटे किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। किसान जैसे–जैसे कमजोर हो रहे हैं, वैसे वैसे बाजार का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। बिचौलियों, सूदखोरों और चालाक व्यापारी उनके मुनाफे का बड़ा हिस्सा निगल रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसका तोड़ ढूंढना कठिन ही है।

ऐसे ही हालात महानदी के किनारे सब्जी और धान की खेती करने वाले किसानों के भी थे। लेकिन धमतरी के इन किसानों ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि बाजार के दिग्गज भौचक हैं। छोटी–छोटी कोशिशों ने ही इन छोटे किसानों को बेहद ताकतवर बना दिया है।

धमतरी से सिहावा की ओर जाने पर एक छोटे से चौराहे से दर्री नाम के गांव की ओर सड़क मुड़ जाती है। बस यही वह गांव है जो एक हजार से ज्यादा किसानों का ऊर्जा केंद्र है। दर्री के आस–पास के करीब दो दर्जन गांवों के छोटे–छोटे किसानों ने मिलकर यहीं के एक छोटे से कमरे में बहुत छोटी सी दुकान खोल रखी है। धमतरी के बड़े–बड़े व्यापारियों का बाजार जिससे सहमा हुआ है, वह यही दुकान है।

असल में सब्जी की खेती करने वाले किसानों ने यह महसूस किया कि बीजों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की खरीदारी में उन्हें हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ज्यादातर किसानों को उधार में ये सब खरीदना पड़ता है, व्यापारी अक्सर उन्हें घटिया दवाइयां भारी–भरकम मुनाफा ऐंठकर बेचते हैं। इन घटिया दवाइयों की वजह से फसलें खराब होती है, दोबारा दवाइयों और खादों पर खर्च करना पड़ता है, सो अलग।

उसे सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत करा लिया। दवाइयों का लाइयेंस हांसिल किया और खोल दी दुकान। अब वे सीधे डीलर से दवाइयां खरीदते हैं और नाम–मात्र के मुनाफे पर संगठन के सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं।

दुकान की खासियत यह है कि यहां सामान किसानों की मांग के अनुरूप ही लाया जाता है। जिस सीजन में जिस चीज की जरूरत होती है, उसकी उपलब्धता पहले ही सुनिश्चित कर ली जाती है। इस तरह बड़े व्यापारियों को बीज–दवाइयों

की कालाबाजारी का भी मौका नहीं मिल पता।

इस छोटी सी दुकान की वजह से अब पूरे इलाके के किसानों को यह पता होता है कि किस चीज की वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए। यदि कभी कभार धमतरी से खरीदारी की नौबत आई तो वे बड़े व्यापारियों से जमकर सौदेबाजी करते हैं। और इसका असर यह है कि धमतरी के व्यापारियों ने भी अपना मुनाफा गिरा दिया है। पहले वे किसान और परिस्थितियां देखकर सामान की कीमत तय किया करते थे, लेकिन अब कीमत बताने से पहले सोचते हैं कि यही चीज दर्री की दुकान में कितने में बेची जा रही होगी।

दर्री की दुकान उदाहरण भर है कि छोटे–छोटे किसानों के संगठित होने का कैसा असर हो सकता है। यहां बना संगठन और भी बड़ी इबारतें लिख रहा है। इस संगठन की बुनियाद भारत सरकार के लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) ने रखी है। एसएफएसी ऐसे ही संगठन पूरे देश में तैयार कर रहा है। इन संगठनों को तैयार करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों की मदद ली गई है। धमतरी के दर्री में किसानों को कोहिजन फाउंडेशन नामक की ऐसी ही एक संस्था ने प्रेरित किया था।

किसानों ने अपने संगठन को सहकारी समिति के रूप देने से पहले यह सीखा कि बाजार की परिस्थितियों और नुकसान का आंकलन कैसे किया जाए और उनसे निपटने की रणनीति कैसे बनाई जाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से लगातार मुलाकातें और बैठकें कीं। इन बैठकों का नतीजा है कि इलाके के किसानों को पता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास उनके लिए कैसी कैसी योजनाएं हैं। कौन–कौन सी मशीनें नाम मात्र की कीमत पर सरकार उन्हें देने के लिए तैयार हैं। परिणाम यह है कि इलाके के खेतों में टमाटर और आलू की छंटनी के लिए ग्रेडिंग मशीनें देखी जा सकती हैं। उनके खेतों में ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई होती देखी जा सकती है। खेतों में बर्मी कंपोस्ट के पिट देखे जा सकते हैं, जिनके जरिए ये किसान रासायनिक खादों में खर्च होने वाली भारी–भरकम रकम बचा रहे हैं। खेतों में मशीनों का अधिकतम उपयोग कर उन्होंने श्रम और समय बचाना सीख लिया है।

दर्री और आस–पास के गांवों के किसानों ने सिर्फ कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, बीजों के बाजारों में ही हमला नहीं बोला है। बल्कि अब उन व्यापारियों को भी बड़ी चोट देने की तैयारी कर रहे हैं, जो इनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर औने–पौने दाम में फसल खरीद लिया करते हैं। किसानों ने जो नया सिलसिला शुरू किया है, उसके तहत अब आस–पास की सभी मंडियों में रेट खंगाला जाने लगा है। जिन मंडियों में अच्छे रेट की खबर होती है, वहां संगठित रूप से फसलें पहुंचाई जाने लगी हैं। सामूहिक रूप से फसलें मंडी ले जाने से एक तरफ जहां बड़े भाड़े की बचत हो रही है, वहीं मनमाफिक दाम पाने के लिए बाजार पर दबाव भी बनता है। बाजार में किसी फसल की कम या ज्यादा आवाक की खबर मोबाइल से हासिल कर उसे पूरे ग्रुप में फैला दिया जाता है। इस आवक के अनुसार ही किसान तय करते हैं कि किस रोज कौन सी सब्जी बाडियों से निकाली जानी चाहिए। इस तरह बाजार की आवक को नियंत्रित करने में किसानों के दखल की शुरुआत भी हो चुकी है।

लेकिन, सफलता की कहानियों का सिलसिला और भी लंबा है। दर्री इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी टमाटर उत्पादक किसानों को। यह फसल जल्दी खराब हो जाती है। बाजार के बड़े व्यापारी इस बात को खूब जानते हैं और इसीलिए उनके दांव–पेंच से किसानों को उपज की सही कीमत अक्सर नहीं मिल पाती। संगठन तैयार होने के बाद किसानों ने बाजार को जवाब देने का तरीका खोज निकाला है। वे अब एक ऐसे मोबाइल वाहन की खरीदी की सोच रहे हैं, जिसमें अनुकूलित वातावरण के जरिए टमाटर जैसी नाजुक फसलें सुरक्षित रखी जा सकें। इसी वाहन के जरिए उसे बाजार तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। वे सामूहिक रूप से गांव में ही एक छोटे कोल्डस्टोरेज की स्थापना के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि ये असंभव नहीं है। सरकार मदद करती है। उन्होंने अधिकारियों से बात कर रखी है।

ऊपर से नीचे तक छोटे किसान

दर्री की सहकारी संस्था के सदस्य सभी एक हजार 64 किसान छोटे और सीमांत हैं। इस बड़े समूह को क्लस्टर कहा जाता है। बड़ा क्लस्टर छोटे–छोटे और भी क्लस्टरों में बांटा गया है। फिर छोटे क्लस्टर समूहों में बांटे गए हैं। इन समूहों से चुने हुए 25 प्रतिनिधि ही सहकारी समिति के केंद्रीय संगठन में पहुंचते हैं। इनमें से 11 सदस्य बोर्ड आफ डायरेक्टर के होते हैं तो शेष प्रमोटर। सभी सदस्य समय–समय पर अलग–अलग छोटे क्लस्टरों में किसानों की बैठकों के जरिए समस्याओं, जरूरतों और आकांक्षाओं का आंकलन करते हैं। बोर्ड आफ डायरेक्टर द्वारा लिए जानने वाले संभावित निर्णयों पर सहमतियां और सुझाव जुटाते हैं। यानी अपना ही उत्पाद बेचते हुए जिन छोटे किसानों को बाजार में व्यापारियों की झिड़कियां सुननी पड़ती थीं, वे आज एक बड़े संगठन के रूप में उनसे नजरें मिलाने की तैयारी में हैं।

देश की ये है तस्वीर

मालिक हैं। इनमें से आधे छोटे और आधे सीमांत हैं। इस आंकड़े को सरल करते हुए बात की जाए तो 100 में से 83 किसान किसी न किसी रूप में शोषण के शिकार हैं। नुकसान झेल रहे हैं। और इस तरह पूरे देश को भी उत्पादन में

किसानों ने सोचा कि क्यों न छोटे–छोटे किसानों से पैसे लेकर गांव में ही ऐसी दुकान खोली जाए, जिसमें किसान ही तय करें कि कौन सी चीज किस दाम में बिकेगी। उन्होंने यही किया। किसानों ने बकायदा अपना संगठन तैयार किया। एक अध्ययन के मुताबिक पूरे देश में 83 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। ये किसान 42 प्रतिशत कृषि भूमि के भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालात की भयावहता इतनी भर नहीं है। छोटे किसानों के खेतों का आकार घटता ही जा रहा है। 1971 में औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था, जो 2006 में सिकुड़कर 1.21 हेक्टेयर रह गया है। इसके बावजूद फसल विविधता के मामले में देश की जरूरतें छोटे किसानों से ही पूरी होती हैं। सब्जियों के उत्पादन के मामले में भी बड़े किसानों से ये कहीं आगे हैं। और यदि खर्चे देखें जाएं तो फसल बचाने, उसे संभालने के लिए बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सतही तौर पर किसी एक किसान की परेशानी, शोषण और नुकसान का अनुमान लगाना तब भी सहज है। लेकिन व्यापक रूप में देश को हो रही क्षति की तस्वीर डरावनी है।

वर्सन

शुरुआत में किसानों को संगठित करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग सोचा करते थे कि किसानों की आड़ में किसी प्रकार की धंधेबाजी होने वाली है। लेकिन किसानों को जब यह बात समझ में आई किस संगठन उन्हीं का है और सारी गतिविधियां उन्हें ही चलानी है तो वे आगे आए। आज जब फायदा नजर आ रहा है तो और भी लोग इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं।

–विजय कश्यप, कर्मचारी, कृषि विकास बहुद्देशीय स्वायत्त सहकारी संस्था, दर्री

संगठन बनाने के बाद अब इलाके के किसानों में खेती को लेकर पहले से ज्यादा उत्साह है। जैसे–जैसे किसानों के खेतों तक नई–नई तकनीक पहुंच रही है, दूसरे किसानों में उन्हें हासिल करने की छटपटाहट बढ़ रही है।

–अर्जुन सोनकर, किसान, ग्राम घरारी (धमतरी)

हम किसानों के बीच सूचना तंत्र को और मजबूत करना चाहते हैं। ताकि किसानों को अपने हित से जुड़ी सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। दवाइयों और बीजों के बाद अब हम खाद का भी लायसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

–दयाराम साहू, अध्यक्ष, कृषि विकास बहुद्देशीय स्वायत्त सहकारी संस्था दर्री

बाजार में सीजन और ग्राहक के हिसाब से व्यापारी रेट अप–डाउन कर देते हैं, लेकिन हमारे गांव की दुकान में हमेशा बाजार से सस्ती चीज मिल जाती है।

–कन्हैयालाल साहू, किसान और पान व्यवसायी, दर्री

एफपीओ – कृषि विकास बहुद्देशीय स्वायत्त सहकारी संस्था, दर्री, धमतरी (छत्तीसगढ़)
स्रोत संस्था – कोहिजन फाउंडेशन

चलते–चलते

कैसा लगा आपको यह प्रवेशांक ? कृषक उत्पादक संगठन की अवधारणा, उसकी क्षमता, उसकी सोच तथा उसकी संभावनाओं व चुनौतियों के बारे में आपकी समझ पहले से कुछ बेहतर हो सकी ?
क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं ?
इस प्रकाशन श्रंखला में आप और कौन से विषयों के बारे में पढ़ना चाहेगें ?
हमें नीचे दिये पते पर या इमेल द्वारा अवश्य लिखें ।

लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ
(भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की संस्था)
पांचवी मंजिल, एनसीयूआई ओडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग,
हॉज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 91 11 2686 2365, फैक्स : 91 11 2686 2367, 2696 6017
ईमेल : sfac@nic.in, वेबसाइट : www.sfacindia.com